**भारत सरकार**
**नागर विमानन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**लिखित प्रश्न संख्या : 3004**
**गुरुवार, 6 अगस्त, 2026/15 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर**

**उड़ान योजना के अंतर्गत विमानन क्षेत्र का विकास**

**3004. श्री मलैयारासन डी.:**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति और तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और परिचालन में लाए गए मार्गों, कार्यशील बनाए गए विमानपत्तनों/हेलीपोर्टों/वाटर एयरोड्रोमों की, विशेषकर तमिलनाडु के कल्लाकुरिची लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, संख्या कितनी है;

(ख) उक्त योजना की शुरुआत से लेकर आज की तिथि तक इसके अंतर्गत वर्ष-वार कुल कितनी निधि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है;

(ग) क्या कम यात्री यातायात या वित्तीय व्यवहार्यता के मुद्दों के कारण कई क्षेत्रीय मार्गों को बंद या निलंबित कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) दूरस्थ, पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में अंतिम छोर तक वायु संपर्क में सुधार करने और सब्सिडी वाले मार्गों की दीर्घकालिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का उड़ान योजना के वर्तमान चरण से आगे इसमें किसी संशोधन या विस्तार का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)**

(क) से (ङ): क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)-उड़ान की शुरुआत से, उड़ान योजना के तहत देशभर में 17 हेलीपोर्टों और 02 वॉटर एयरोड्रोमों सहित 95 असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों को जोड़ने वाले कुल 679 आरसीएस मार्गों को कार्यशील किया गया है।

तमिलनाडु के कल्लाकुरिची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित किसी भी हवाईअड्डे को उड़ान योजना के तहत विकास के लिए चिन्हित नहीं किया गया है।

क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) के अंतर्गत चिह्नित असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों/हेलीपोर्टों/वॉटर एयरोड्रोमों के पुनरुद्धार और विकास के लिए, इस योजना के पहले चरण में 4500 करोड़ रुपये और दूसरे चरण में 1000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। आरसीएस योजना के तहत हवाईअड्डों के पुनरुद्धार/विकास के लिए अब तक 4,839.48 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

इस योजना के तहत, परिचालन और एयरलाइन संबंधी मुद्दों के कारण 156 मार्गों ने अपने 3 साल के वीजीएफ समर्थन कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही अपनी सेवाएं बंद कर दीं हैं।

टियर 2 और टियर 3 शहरों और देशभर के दूरदराज के क्षेत्रों में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना का अगला चरण दिनांक 04.07.2026 को शुरू किया गया था, जिसमें अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों और 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करने का लक्ष्य था। इस योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक 28,840 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें एयरोड्रोम विकास के लिए

12,159 करोड़ रुपये और पर्वतीय, पूर्वोत्तर एवं आकांक्षी (एचआईएनईआर) राज्यों/जिलों में 200 हेलीपोर्टों के विकास के लिए 3,661 करोड़ रुपये शामिल हैं।

******